महामहिम राज्यपाल
सरदार श्री हुकम सिंह का अभिभाषण
21 मार्च, 1972

माननीय सदस्यगण,

1. पाँचवें आम चुनाव के बाद नई विधान सभा के इस प्रथम सत्र के अवसर पर आपको सम्बोधित करते हुए मुझे अत्यन्त हर्ष हो रहा है। आप सबकी विजय के लिए मैं बधाई देता हूँ और आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस पाँचवें विधान सभा के आम चुनावों का शान्तिपूर्ण एवं सुचारु रूप से सम्पन्न हो जाना राष्ट्र के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण घटना है। इन चुनावों से मतदाताओं की परिपक्वता, अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता एवं जनतंत्र में सुदृढ़ आस्था और अधिक स्पष्ट हो गई है। वास्तव में भारतीय मतदाताओं ने विश्व के सबसे बड़े जनतंत्र के अंग होने का दायित्व पूर्ण रूप से निभाया है जो एक गौरव की बात है।

2. राज्य में पाँचवें आम चुनाव सद्भावना एवं सुचारु रूप से सम्पन्न हुए। इस बार विधान सभा की 184 सीटों में से एक सीट पर निर्विरोध चुनाव हो जाने के बाद 183 सीटों के लिए चुनाव हुआ और इन सीटों के लिए चुनाव मैदान में 874 उम्मीदवार थे। 18 हजार 618 मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं ने मतदान किया जो कुल मतदाताओं की संख्या का 58.27 प्रतिशत रहा। इस महत्त्वपूर्ण कार्य को संचालित करने के लिए मतदान केन्द्रों पर विभिन्न स्तरों के 35 हजार राज्य कर्मचारियों को नियोजित किया गया। इतने व्यापक कार्य को इस तरह शान्ति, शीघ्रता एवं सुगमता से सम्पन्न करने के लिए चुनाव-कार्य में नियोजित सभी राज्य कर्मचारीगण प्रशंसा के पात्र हैं।

3. चुनाव के सन्दर्भ में सरकार का दायित्व और अधिक बढ़ गया है। गरीबी हटाने और समाजवाद के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये और अधिक व्यापक कार्यक्रम लागू करने के लिए सरकार कृतसंकल्प है। भारतीय संविधान में 26वें संशोधन के द्वारा प्रीवीपर्स और राजाओं के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया है। देश में इसका सबसे अधिक एवं अनुकूल प्रभाव राजस्थान में पड़ा है। यह समानता पर आधारित समाज की स्थापना की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीनों को जमीन आवंटित करने का कार्यक्रम और तेजी से लागू करने का दायित्व सरकार पर है। साथ ही कृषि-भूमि पर सीलिंग कानून को भी कड़ाई से लागू करने के लिए सरकार कृत-संकल्प है। ग्रामीण जनता को आवास हेतु जमीन देने का कार्यक्रम भी और तेजी से लागू किया जा रहा है। उत्पादन-कार्यों के लिए अधिक एवं सुविधापूर्वक ऋण दिलवाने की व्यवस्था की

जा रही है जिससे पैदावार भी बढ़े और ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा रोजगार की सुविधायें हों। पंचायतों के चुनाव लम्बे अर्से से रुके पड़े हैं इनको सरकार शीघ्र करवाने की व्य रही है। सरकार का निश्चय है कि शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित कर एक विधेयक इसी वर्ष इस सदन में प्रस्तुत किया जावे। कच्ची बस्तियों में रहने वाली लिए पानी, बिजली व सड़कों की व्यवस्था करने के लिए पूर्व में दिये गये आश्वासनों हद तक पूरे करने का प्रयास किया गया है और शेष रहे कार्यों को भी शीघ्र पूरा किय है। विश्वविद्यालयों की कार्य प्रणाली में सुधार एवं उनके प्रशासन में विद्यार्थियों प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से भी एक विधेयक राज्य सरकार इसी वर्ष इस सदन में प्रस्तु तकनीकी क्षेत्र में व्याप्त बेरोजगारी समस्या के निवारण हेतु सरकार और अधिक प्रयत्न राज्य के सीमित वित्तीय साधनों के सम्बन्ध में राज्य सरकार अन्तरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संस्थाओं से विशेष योजनाओं पर अधिक सहायता प्राप्ति का प्रयत्न कर रही है जिससे के विकास की रफ्तार अधिक तेज हो।

४. हाल ही में हुए ऐतिहासिक भारत-पाक संघर्ष का भी मैं विशेष रूप से उल्लेख चाहूँगा। देश पर थोपे गये इस युद्ध से हमें केवल सैनिक सफलता ही नहीं मिली है बल्कि प्रिय एवं मौलिक सिद्धान्तों जैसे धर्मनिरपेक्षता एवं जनतंत्र की महान विजय हुई है। ३ दि १९७१ को पाकिस्तान द्वारा अचानक हमले में राजस्थान के कुछ शहरों पर भी बमबारी हमारी सेना एवं सीमा सुरक्षा दल ने स्थिति का हिम्मत व बहादुरी से मुकाबला कि अधिकांशतः युद्ध को पाकिस्तान के क्षेत्र में सीमित रखा। लोंगेवाला की तरफ पाकिस्ता आक्रामक कार्यवाही की उसमें उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा और उसे पीछे हटना पड़ा इस में और विशेष रूप से सीमा-क्षेत्रों की जनता का मनोबल सराहनीय रहा। राज्य स युद्ध के दौरान सेना को पानी, यातायात, संचार, चिकित्सा एवं अन्य प्रकार की सब आ सुविधायें तथा समर्थन समय पर उपलब्ध कराने में कोई कसर नहीं रखी और युद्ध के सेना और राज्य सरकार के बीच लाल-मेल सराहनीय रहा। इस युद्ध में वीरगति पा योद्धाओं एवं नागरिकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ तथा युद्ध में घायल हुए योद्धाओं के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना हूँ। वीरगति प्राप्त योद्धाओं के आश्रितों एवं अपंग हुए योद्धाओं को राज्य सरकार द्वारा प्रकार की सहायता दी जा रही है, जैसे नकद पुरस्कार, भूमि-आवंटन आदि। भारत सरक सम्मानित अन्य योद्धाओं को भी राज्य सरकार नकद अनुदान, भूमि-आवंटन आ सम्मानित कर रही है।

५. भूमिहीनों को भूमि का आवंटन, काश्तकारों तथा ग्रामीण जनता के आर्थिक एवं उनके जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने की ओर सरकार हमेशा प्रयत्नशील रही है। भूमि-आ के साथ-साथ ऐसे भूमिहीनों, जिन्होंने राजकीय भूमि पर गैर कानूनी कब्जा कर रखा

[illegible] सहानुभूतिपूर्वक विचार कर निर्णय लिया गया है कि 1 जनवरी, 1971 तक जिन [illegible] सरकारी कृषि-भूमि पर अनधिकृत कब्जा कर काश्त की है उनके कब्जों को भी [illegible] दिये जावें। इसके साथ-साथ अधिक-से-अधिक भूमिहीनों को निर्धारित सीमा [illegible] करने हेतु भूमि आवंटन नियमों में भी ढील बर्ती जाकर ये सीमाएँ कम कर दी गई है।

6. भूतपूर्व नरेशों की भूमि अवाप्त करने हेतु बनाये गये अधिनियम को राजस्थान उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई और अधिनियम के कुछ प्रावधानों को उच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया जिसके फलस्वरूप नरेशों की भूमि अवाप्ति सम्बन्धी कार्य में अड़चन पैदा हुई। [illegible] भूमि के अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है, और अब तक 57 हजार 964 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की जा चुकी है जिसमें से 8 हजार 546 एकड़ भूमि भूमिहीन कृषकों को वितरित की जा चुकी है। ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की समस्या को हल करने की दृष्टि से खातेदारी भूमि को आबादी में एक निश्चित सीमा तक निःशुल्क परिवर्तित कराने हेतु नियम जारी किये गये हैं। [illegible] क्षेत्रों में भी सिवाय चक भूमि या गोचर भूमि पर अथवा गैर मुमकिन या वन-भूमि [illegible] के मकान तथा बाड़े बना लिये हैं ऐसे व्यक्तियों को भी राहत देने की दृष्टि से कुछ [illegible] छोड़कर 500 वर्ग गज तक भूमि में 31 दिसम्बर, 1970 के पूर्व निर्मित ऐसे मकान [illegible] का भी नियमन करने का प्रावधान किया गया है।

7. उपनिवेशन विभाग द्वारा राजस्थान नहर योजना क्षेत्र के प्रथम चरण में लिफ्ट क्षेत्र के [illegible], बीकानेर, लूणकरणसर के गाँवों में लगभग 99 हजार बीघा जमीन का सर्वेक्षण किया गया है। विभाग द्वारा 5 हजार 632 बीघा भूमि का एकीकरण भी किया गया है। वर्ष 1971-72 में विशिष्ट श्रेणी के लगभग 45 व्यक्तियों को 1 हजार 73 एकड़ भूमि का अस्थायी आवंटन किया गया तथा चालू वर्ष में 11 कृषि-स्नातकों को 275 बीघा क्षेत्र का आवंटन हो चुका है। [illegible] से आये विस्थापितों के करीब 257 परिवारों को एक हजार 400 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया है। राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में गैर-दखिलकारों को कृषि-भूमि का आवंटन किया गया है और करीब ऐसे 793 परिवारों को लगभग 17 हजार बीघा भूमि आवंटित की जा चुकी है। उपलब्ध सिंचाई-क्षमता का पूर्ण सदुपयोग करने हेतु वर्ष 1971-72 में 14 हजार भूमिहीन परिवारों को कृषि-भूमि का अस्थायी आवंटन किया गया जिनमें 10 हजार सवर्ण और 4 हजार अनुसूचित जाति के परिवार हैं। कुल 4 लाख 2 हजार बीघा भूमि कृषि हेतु आवंटित की गई तथा 9 हजार परिवारों को 1 लाख 55 हजार बीघा भूमि का नवीनीकरण किया गया।

8. राजस्थान में वनों का विकास-कार्य प्रगति पर है। चालू वित्तीय वर्ष में चारागाह-सुधार, परिभ्रांपित (डिग्रेडिड) वनों का पुनर्वास, आर्थिक वृक्षारोपण, राजस्थान नहर परियोजना [illegible] वन-विकास, वन्य पशु-पक्षियों का संरक्षण, वन सीमांकन तथा बन्दोबस्त के पुराने कार्यों की कार्ययोजना का पुनर्निर्माण, वनों की सुरक्षा और पहाड़ी कन्दरा तथा रेतीले क्षेत्रों में भू-संरक्षण

के कार्यक्रम क्रियान्वित हो रहे हैं। ऐसे ही कार्य 1972-73 में चलेंगे। इसके अतिरि केन्द्रीय योजनाएँ भी चल रही हैं। बाड़मेर जिले में मरुस्थल विकास योजना के अ चारागाह-सुधार कार्य, परिभाषित वनों के पुनर्वास, ऊसर भूमि-सुधार कार्य, सड़कों के वृक्षारोपण व पौध-शालाओं के निर्माण-कार्य लेने व पूर्व में लिये गये कार्यों को पूर्ण क योजना है जिसके लिए लगभग 35 लाख रुपये की राशि अगले वित्तीय वर्ष में व्यय की वन संसाधन सर्वेक्षण की केन्द्रीय योजना भी चल रही है। लकड़ी, कोयला तथा बल्लियों के में ठेकेदारी प्रथा 1968 में समाप्त की गई तब से विभागीय प्रणाली चालू है जिससे आय वन-श्रमिकों को रोजगार देने में लगातार वृद्धि हो रही है। लकड़ी व कोयले की कीमतों में लाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 14 विक्रय-केन्द्र भी स्थापित किये हैं।

9. बहुउद्देशीय, मध्यम एवं लघु-सिंचाई योजनाओं का कृषि के क्षेत्र में काफी मह वर्ष 1971-72 में सिंचाई योजनाओं के लिए 21.95 करोड़ रुपये का प्रावधान था जो ग से 70 प्रतिशत अधिक था। भाखरा नहर का निर्माण-कार्य सम्पूर्ण हो चुका है और इसी में, व्यापक रूप से सिंचाई की जा रही है। इस नहर से 2 लाख 28 हजार हैक्टर क्षेत्र वर्ष सिंचाई होने का प्रावधान था किन्तु अब इस नहर से 2 लाख 48 हजार हैक्टर क्षेत्र वर्ष सिंचाई की जा रही है। इसी प्रकार चम्बल घाटी योजना के अन्तर्गत कोटा बैराज त व दांई नहरों का निर्माण-कार्य भी पूरा किया जा चुका है किन्तु बाद में सीपेज की सम लिए नाला बनाने, नहरों को पक्का बनाने आदि के कार्य अभी पूरे किये जा रहे हैं। इस से चालू वर्ष में 1.51 लाख हैक्टर भूमि में सिंचाई होने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त गु नहर परियोजना एवं माही योजना का कार्य चल रहा है। राज्य में लघु-सिंचाई योजनाओं इस वर्ष 200 लाख रुपये का प्रावधान था जिसके अनुसार कार्य प्रगति पर है। मध्यम योजनाओं में बड़गांव, औराई, खारी फीडर, मेई आवम, पंजा फीडर तथा जैतपुरा आ कार्य सुचारु रूप से चल रहा है। कुछ बांधों को जो सिंचाई के लिए उपयोगी हैं, ऊंचा का कार्य भी किया जा रहा है।

10. राजस्थान नहर राज्य के भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योजना है और बीकानेर, गंगानगर व जैसलमेर जिलों में लगभग 31.24 लाख एकड़ भूमि में वार्षिक की जा सकेगी। युद्ध की गतिविधियों के कारण इस कार्य में कुछ रुकावटें आई किन्तु मुख्य नहर के प्रथम चरण में 88 मील का कार्य पूर्ण हो चुका है और 88 से 124 मी का कार्य प्रगति पर है। इस वर्ष जनवरी तक 3.35 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई हो और आशा है कि वर्ष के अन्त तक दोनों फसलों में लगभग 4.40 लाख एकड़ भूमि की हो सकेगी। गत वित्तीय वर्ष के अन्त तक इस नहर के निर्माण-कार्य पर कुल 72.36 करो व्यय हो चुके हैं।

11. इसी प्रकार व्यास परियोजना है जिसमें व्यास नदी के जल का सिंचाई व वि

... किया जायेगा। यह योजना दो यूनिटों में विभाजित है। पहली यूनिट व्यास ... दूसरी योग पर व्यास बांध का निर्माण। पहली यूनिट से मुख्यतया बिजली का ... दूसरी से राजस्थान को सिंचाई व बिजली-उत्पादन के लिए बारह मासी पानी ... दोनों यूनिटों के पूरा होने पर राजस्थान को अपने हिस्से में करीब 1,50 मेगावाट ... हो सकेगा। दोनों यूनिटों का कार्य तीव्र गति से प्रगति पर है और सम्भवतः ... पूर्ण हो जायेगा। राजस्थान नहर सहित सभी सिंचाई योजनाओं से राज्य में ... लाख हैक्टर भूमि में सिंचाई होगी।

... क्षेत्र में ट्रान्समिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली के विस्तार को सर्वाधिक ... गई है। विभिन्न विद्युत योजनाओं से बिजली के उत्पादन में वृद्धि के फलस्वरूप ... बिजली (फर्म पावर) वर्ष 1970-71 में 248 मेगावाट से बढ़कर सन् 1971-72 में ... मेगावाट हो गई है। वर्ष 1971-72 में करीब 1 हजार कूओं को बिजली पहुँचाई ... तथा 1 हजार नई बस्तियों का विद्युतीकरण भी हो जायेगा। उद्योगों को भी ... उपलब्ध होगी। हाल ही में विद्युत मण्डल ने अजमेर की गैर सरकारी बिजली ... की मिलकियत को भी खरीद लिया है और अब वहां बिजली का वितरण मण्डल ... कर रहा है।

... बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से सहायता प्राप्त करने के लिए विशेष योजना ... सितम्बर, 1970 में स्थापित किया गया है। इस प्रकोष्ठ द्वारा राजस्थान नहर के ... पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए 200 करोड़ रुपये की एक योजना बनाई ..., जो ... बैंक के विचाराधीन है। पशुधन के विकास क्षेत्र में भी 120 करोड़ रुपये की दो ... तैयार की गई हैं जिनकी भारत सरकार के विशेषज्ञों द्वारा जाँच की जा रही है। दुग्ध ... के लिए भी "ऑपरेशन-फ्लड" नामक 4 करोड़ रुपये की योजना तैयार की गई है ... राजस्थान के क्षेत्रों को लाभ होगा। एग्रीकल्चरल फिनांस कारपोरेशन ... फाइनेन्स कारपोरेशन द्वारा इस प्रकोष्ठ से बनाई गई 7 लघु सिंचाई योजनाएँ इसी ... ली गई हैं व अन्य 12 योजनाओं के स्वीकृत होने की आशा है। इसी प्रकार की ... के विकास के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध होगी।

... कृषि के क्षेत्र में खाद्य-उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है, जहां वर्ष 1970-71 में 76 ... खाद्यान्नों का उत्पादन होने का अनुमान था वहां वास्तविक उत्पादन 88.12 लाख ... हुआ। वर्ष 1971-72 में राज्य के कुछ जिलों में प्रतिकूल मौसम व कुछ फसलों में बीमारियों के ... खाद्यान्नों का उत्पादन सामान्य ही रहने की आशा है। जैसा कि मैंने पहले भी ... किया था कि राज्य में खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ाने हेतु कृषि की आधुनिक विधियों को ... अधिक-से-अधिक अपनाया जा रहा है। अधिक उत्पादन देने वाली फसलों का कार्यक्रम ... बढ़ाया जा रहा है। जहां वर्ष 1970-71 में 7 लाख हैक्टर भूमि में इन फसलों का

उत्पादन किया गया था वहां इस वर्ष 8 लाख हैक्टर क्षेत्र में उत्पादन किया गया है। वर्ष 1972-73 में यही कार्यक्रम लगभग 12 लाख हैक्टर भूमि में लेने की योजना है।

15. उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए उर्वरक का प्रयोग प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है। वर्ष 1970-71 में 2 लाख 81 हजार टन विभिन्न उर्वरकों का वितरण किया गया था व 1971-72 में 3 लाख 83 हजार टन का वितरण हो जाने का अनुमान है। यह वृद्धि 32 प्रतिशत है। वर्ष 1972-73 में लगभग 4 लाख 50 हजार टन उर्वरकों की खपत और 25 से 30 प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़ोतरी होगी। राज्य में उर्वरकों का प्रयोग बढ़ाने हेतु एक नई ... को अपनाया गया है जिसे "फोलियर अप्लीकेशन" कहते हैं और जिसमें पत्तियों द्वारा नत्रजन लेते हैं। वर्ष 1971-72 में यह कार्यक्रम गेहूँ की फसल पर लगभग 1 लाख 75 ... हैक्टर भूमि में लिया गया है। इसके अतिरिक्त इसके परिणाम अन्य फसलों पर जैसे कपास ... पर बहुत ही संतोषजनक रहे हैं। वास्तव में कपास के ऊपर इस पद्धति द्वारा उर्वरक के छि... का कार्य भारतवर्ष में सबसे पहले राजस्थान में प्रारम्भ किया गया।

16. पौध-संरक्षण कार्यों को भी काफी बढ़ावा दिया गया है। सरसों में चेपा को ... के लिए अलवर, भरतपुर व सवाई माधोपुर जिलों में 34 हजार 400 हैक्टर भूमि में पौध-सं... कार्य किया गया। इसके अतिरिक्त फसलों को बचाने हेतु अलवर जिले में 2 हजार 856 ... भूमि में तथा श्रीगंगानगर जिले में 11 हजार 200 हैक्टर कपास में हवाई जहाज द्वारा दवा... का छिड़काव किया गया। वर्ष 1972-73 में करीब 40 हजार हैक्टर क्षेत्र पर हवाई ज... द्वारा दवाइयां छिड़क कर पौध-संरक्षण कार्य करने का लक्ष्य रखा गया है और कुल पौ... संरक्षण-कार्य का लक्ष्य 42 लाख हैक्टर का है। देश में कपास व तिलहन की फसलों में आ... निर्भरता लाने के लिए कई नई कार्यक्रम राज्य में भी आरम्भ किये गये हैं। वर्ष 1971-72 ... श्रीगंगानगर क्षेत्र में लम्बे रेशेवाली कपास की सघन कृषि-योजना 40 हजार हैक्टर भूमि ... केन्द्रीय सहायता से आरम्भ की गई है। वर्ष 1972-73 में इस कार्यक्रम को 60 हजार है... भूमि में चालू करने का लक्ष्य है। इसी प्रकार राजस्थान नहर क्षेत्र में ऐसी ही किस्म की कपा... की सघन कृषि लगभग 20 से 30 हजार हैक्टर भूमि में करने की एक नई केन्द्रीय योजना ... की गई है। वर्ष 1971-72 में श्रीगंगानगर जिले में कपास की बिक्री में कुछ कठिनाई आई ... एक तो उत्पादन अधिक होने व दूसरे राष्ट्रीय संकट के आ जाने के कारण मंडियों में खरीद... न होने से मूल्य एकदम गिर गये, परन्तु शीघ्र ही राज्य सरकार के प्रयासों से भारतीय कपास नि... की ओर से खरीद का काम शुरू कर दिया गया जिससे कृषकों को काफी राहत मिली। ऐ... खरीद की व्यवस्था आगामी वर्ष भी होगी।

17. तिलहन की फसलों का उत्पादन बढ़ाने हेतु केन्द्रीय सहायता से मूंगफली का सघ... कृषि-कार्यक्रम आरम्भ किया गया है। वर्ष 1971-72 में यह योजना चित्तौड़गढ़ व राजस्था... नहर क्षेत्र में लागू की गई है। वर्ष 1972-73 में इन क्षेत्रों के अतिरिक्त इसे अजमेर क्षेत्र में ला...

किया जायेगा। ग़न्नों की पैदावार को बढ़ावा देने के लिए राज्य के विभिन्न भागों में सघन कृषि-[illegible] की योजना है इसके अतिरिक्त एक नई फसल 'सूर्यमुखी' जिसमें तेल की [illegible] अधिक होती है, के प्रदर्शन 1971-72 में लगाये गये थे, उसके परिणाम आशाजनक प्राप्त हुए हैं। इस कार्यक्रम को वर्ष 1972-73 में और भी बढ़ावा दिया जायेगा।

18. चीनी के उत्पादन की दृष्टि से यह वर्ष देश के लिए अनुकूल नहीं रहा। भारत सरकार द्वारा मई, 1971 में चीनी पर लगे सभी प्रतिबन्ध समाप्त कर दिये जाने से यहां भी उचित मूल्य की दुकानों से चीनी का वितरण समाप्त कर दिया गया था किन्तु कुछ ही माह बाद स्थिति में [illegible] के फलस्वरूप राज्य में पुन: चीनी का वितरण उचित मूल्य की दुकानों के [illegible] से किये जाने की व्यवस्था की गई।

19. 1970-71 में कृषि ऋण-दात्रि सहकारी समितियों द्वारा अपने सदस्यों को 16.33 करोड़ रुपये के अल्प व मध्यमकालीन ऋण वितरित किये गये। 1971-72 में इससे अधिक ऋण वितरण की आशा है। वर्ष 1972-73 में 23 करोड़ रुपये का ऋण वितरित करने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त दीर्घकालीन ऋण भी वितरित किये गये। 1971-72 में ये ऋण [illegible] 6.50 करोड़ रुपये के होंगे तथा वर्ष 1972-73 में 9.50 करोड़ रुपये के दीर्घकालीन ऋण दिये जाने का लक्ष्य है। कताई मिल, गुलाबपुरा संभवतया अप्रेल, 1972 में उत्पादन-कार्य प्रारम्भ करेगी। क्रय-विक्रय संघ द्वारा 6 चावल मिलें स्थापित की जा रही हैं जिनमें से 4 मिलों ने कार्य प्रारम्भ कर दिया है। इसके अतिरिक्त संघ द्वारा नागौर में 24 लाख रुपये का ग्वार से गोंद बनाने का कारखाना स्थापित किया जा रहा है।

20. वर्ष 1971-72 में जोधपुर में दुग्ध-वितरण योजना की क्रियान्विति चालू रही जो कि आगामी वर्ष में पूर्ण होगी। शुरू में 1 हजार लीटर दूध रोजाना वितरण करने की पायलेट योजना चलाई जायेगी व बाद में पूर्ण योजना, जिसमें 20 हजार लीटर दूध वितरण करने की क्षमता हो, चालू की जायेगी। भेड़ों की नस्ल सुधारने के लिए विदेशों से अच्छी किस्म की भेड़ें मंगवाई जा रही हैं। [illegible] जिले के फतेहपुर में एक वृहत् स्तर पर भारत सरकार की सहायता से भेड़-प्रजनन केन्द्र की योजना सिद्धान्तत: स्वीकार हो चुकी है।

21. औद्योगिक क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं एवं सहायताओं से [illegible] प्रभाव पड़ा है। सन् 1970 तक की कुल पंजीकृत औद्योगिक इकाइयां, जो कि [illegible] हजार [illegible] थीं, वर्ष 1971 तक बढ़कर 8 हजार 970 हो गई। 1970 व 1971 में क्रमश: 16 व [illegible] लेटर आफ इन्टेण्ट अथवा सीओबी लाइसेन्स अथवा लाइसेन्स राज्य सरकार की सिफारिश पर बड़े उद्योगों को मिले। राजस्थान वित्त निगम द्वारा इन उद्योगों को लगवाने के [illegible] प्रयास जारी हैं। चालू वित्तीय वर्ष में फरवरी, 1972 तक 205 संस्थानों को 244.75 लाख रुपये का ऋण दिया जा चुका है और वर्ष के अन्त तक लगभग 280 लाख रुपये के ऋण दिये जाने की संभावना है जब कि गत वर्ष इस निगम के माध्यम से 182 संस्थानों को 247.14

लाख रुपये का ऋण दिया गया था। ऋण प्राप्तकर्ता संस्थानों में लघु-उद्योग का बाहुल्य है। सरकार एवं औद्योगिक विकास बैंक के सहयोग से निगम द्वारा राज्य के 16 पिछड़े जिलों में शर्तों पर उद्योगों की स्थापना के लिए ऋण देने की योजना का क्रियान्वयन प्रगति पर है। से अलवर व जोधपुर जिलों में 10 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान विभिन्न नवीन उद्योगों को सरकार द्वारा केन्द्र से प्राप्त धनराशि के आधार पर दिया जायेगा। वित्त निगम द्वारा सुगम योजना भी लागू की गई है जिसके अन्तर्गत एक संस्थान को डेढ़ लाख रुपये तक का ऋण प्रतिशत ब्याज की दर पर उपलब्ध हो सकता है। प्रशिक्षित इन्जीनियरों के लिए और अधि सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं। अप्रेल, 1970 से फरवरी, 1972 के अन्त तक निगम 53 इन्जीनियरों को उद्योग स्थापित करने के लिए 62.40 लाख रुपये दिये गये हैं। अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा भी इकाइयों को स्थापित करने के लिए ऋण दिया गया है।

22. राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम द्वारा अलवर में स्कूटर कारखाना लगाया जा रहा है। इसकी उत्पादन क्षमता 24 हजार स्कूटर प्रति वर्ष होगी। अतिरिक्त सोडा एश, कैल्शियम कार्बाइड, ग्लास बोटल्स एवं कन्टेनर्स व सिन्थेटिक क्रापोल तथा फ्लोराइड व थ्री-व्हिलर्स उद्योग जिनके लिए निगम को भारत सरकार द्वारा लैटर आ इन्टेण्ट मिल चुके हैं, को लगाने पर भी निगम विचार कर रहा है। निगम द्वारा जयपुर, को जोधपुर, उदयपुर, अलवर, चिड़ावा, पाली इत्यादि में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया ग है एवं किया जा रहा है। निगम ने हाफ एण्ड ओन यॉर इण्डस्ट्रीज स्कीम के अन्तर्गत 4 उद्यो इन्जीनियरों के साथ सहयोग कर, लगाये हैं। राजस्थान लघु उद्योग निगम ने भी अपनी प्रग का क्रम चालू रखा है। निगम द्वारा मशीनरी के लिए हायर-पर्चेज स्कीम हाल में लागू की है। निगम ने अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भी भाग लिया। यह उल्लेखनीय है कि वित्त निगम, राजस्था राज्य औद्योगिक खनिज विकास निगम एवं लघु उद्योग निगम ये तीनों सरकारी निगम लगा मुनाफे में चल रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान के सभी जिलों में औद्योगिक सर्वेक्षण कार्य विभिन्न संस्थानों के द्वारा करवाया जा रहा है जो सम्भवतः दो वर्ष में पूरा हो जायेगा। रा सरकार द्वारा तकनीकी क्षेत्र में व्याप्त बेरोजगारी के निवारण हेतु भारत सरकार से सम्पादित समर्थित क्रैश-प्रोग्राम की मदें क्रियान्वित विभिन्न निगमों द्वारा करवाई जा रही है। भारत सरका से इस योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में 3.7 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं। आगामी वर्ष इस योज पर और अधिक कार्य होने की सम्भावना है।

23. भारत सरकार द्वारा ग्रामीण औद्योगिक विकास योजना के अन्तर्गत टोंक व बांसवाड़ा जिलों में भी प्रारम्भिक कार्य शुरू किये जा चुके हैं। सूती कपड़े की एडवर्ड मि ब्यावर का नियंत्रण भी राज्य सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार ने राष्ट्रीय टेक्सटाइल्स निगम दे दिया है व इस मिल एवं महालक्ष्मी मिल, ब्यावर के पुनर्निर्माण का व्यापक कार्य राष्ट्री टेक्सटाइल निगम व राज्य सरकार के निश्चित साधनों से शुरू किया गया है।

24. ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए इस वर्ष एक केन्द्रीय [illegible] योजना लागू की गई है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक जिले में एक हजार व्यक्तियों को रोजगार [illegible] 10 माह के लिए मिलेगा। एक जिले में इस योजना के अन्तर्गत 12 लाख 50 हजार [illegible] व्यय का प्रावधान है। यह योजना 1972-73 में भी लागू रहेगी। इस योजना के अन्तर्गत जिलों में लघु सिंचाई, भू-संरक्षण, सड़क-निर्माण, वन व छोटे विकास आदि के कार्यों [illegible] लिया जा चुका है। इस योजना के अन्तर्गत अब तक 998 निर्माण-कार्य स्वीकृत [illegible] जा चुके हैं। वर्ष 1971-72 में केयर-फीडिंग प्रोग्राम के अन्तर्गत 128 पंचायत समितियों [illegible] लाख बच्चों को मध्याह्न भोजन देने का लक्ष्य था। वर्ष 1972-73 में इसको बढ़ाकर प्रति [illegible] लाख बच्चों को भोजन देने की योजना है।

25. राज्य में पंचायतों के स्वरूप व सीमाओं आदि के सुधार व पुनर्गठन हेतु उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है।

26. वर्ष 1970-71 में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रारम्भ किये गये ग्राम्य निर्माण कार्यक्रम [illegible] अब नया नाम 'अकाल प्रभावित क्षेत्रीय कार्यक्रम' है, के अन्तर्गत राज्य के 10 [illegible] अभावग्रस्त जिलों को चुना गया जिनके नाम हैं – जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, बीकानेर, चूरू, [illegible], नागौर, पाली, डूँगरपुर एवं बांसवाड़ा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक जिले [illegible] चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक दो करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान भारत सरकार [illegible] है। इसके अन्तर्गत इस प्रकार के उत्पादक कार्य किये जाने हैं जिनसे भविष्य में [illegible] स्थिति की गम्भीरता इन जिलों में कम होगी। वर्ष 1970-71 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सिंचाई, वन एवं सड़कों के कार्य भारत सरकार से स्वीकृत कराये गये, लेकिन यह [illegible] प्राप्त होने के कारण वर्ष 1970-71 में कार्यों के क्रियान्वयन में विशेष प्रगति नहीं हो सकी। इन स्वीकृत कार्यों का क्रियान्वयन वर्ष 1971-72 में सन्तोषपूर्वक चल रहा है। [illegible] की सिंचाई, सड़क, वन, भू-संरक्षण एवं पेयजल की क्षेत्रीय योजनाओं के नये कार्य वर्ष 1971-72 में भारत सरकार से स्वीकृत कराये गये। इस प्रकार अब तक 16 करोड़ रुपये [illegible] के कार्यों की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी है। शेष प्रावधान के अन्तर्गत [illegible] जैसे सामूहिक नल-कूप योजना आदि को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत कराने के प्रयास जारी हैं।

27. राजस्थान नहर योजना क्षेत्र में 20 तथा अन्य स्थानों में 10 प्राथमिक पाठशालाएँ [illegible] खोली गईं। इसके अतिरिक्त राज्य में 400 प्राथमिक शालाओं को उच्च प्राथमिक स्तर [illegible] क्रमोन्नत किया गया। 90 पाठशालायें जो पंचायत समितियों द्वारा और 52 पाठशालायें जो [illegible] द्वारा चलाई जाती थीं को राज्याधीन लिया गया। 203 माध्यमिक शालाओं को [illegible] माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत किया गया। भरतपुर व भीलवाड़ा में छात्राओं हेतु और सवाई

माधोपुर में छात्रों हेतु महाविद्यालय प्रारम्भ किये गये। इस वर्ष राज्य में शिक्षकों में बेरोजग कम करने के लिये केन्द्रीय सरकार के योगदान से 2,630 अध्यापकों को रोजगार देने हेतु सृजित किये गये हैं। छात्राओं तथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति विद्यार्थियों की शिक्षा संख्यात्मक एवं गुणात्मक विकास करने सम्बन्धी योजनायें जैसे निःशु पुस्तकें, लेखन-सामग्री आदि की योजनायें प्रारम्भ की गई हैं। इस खर्चे के लिये केन्द्रीय सर से शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त किसान साक्षरता योजना व शिक्षा क्षेत्र प्रगति हेतु प्रोजेक्ट्स केन्द्रीय सरकार की पूर्ण सहायता से चालू किये गये। आयु वर्ग 6-1 11-14 एवं 14-17 में स्कूल जाने वाले छात्रों का प्रतिशत 58.8, 27.4 तथा 12.4 हो का अनुमान है। शिक्षा को समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिये आगामी में विशेष प्रयत्न किये जायेंगे।

28. इस वर्ष 13 जिला-स्तरीय अस्पतालों का उच्चीकरण किया गया तथा निर्धा लक्ष्य के अनुसार 25 नई डिस्पेन्सरीज खोली गई जिनमें से 24 सुदूर ग्रामीण-क्षेत्रों में हैं। 9 मातृ एवं शिशु कल्याण-केन्द्रों की स्थापना की जा रही है। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन योजना अन्तर्गत 2 नई क्लिनिक्स की स्थापना जालोर और नागौर में भी कर दी गई है। परिवार नियो योजना के अन्तर्गत फरवरी, 1972 तक 2 लाख 25 हजार व्यक्तियों के नसबन्दी एवं । ला 26 हजार लूप-प्रविष्टि की जा चुकी है। चेचक-उन्मूलन योजना के अन्तर्गत लगभग 28 ला व्यक्तियों के टीके लगाये गये हैं। राज्य में रोहे-नियंत्रण एवं कुष्ठ रोग निवारण की योजना प्रग पर है।

29. नगरीय क्षेत्र की पेय-जल समस्याओं के निवारणार्थ चालू वर्ष में 336 लाख रुपये की 19 नई योजनाओं का कार्य हाथ में लिया गया है तथा इस वर्ष में लगभग 11 नई नगरी जलप्रदाय योजनाओं के कार्य सम्पूर्ण होने की संभावना है। ग्रामीण क्षेत्र में भी पीने का पा उपलब्ध कराने में राज्य सरकार सजग रही है। वर्ष 1971-72 में 75 एवं 1972-73 में 9 और ग्रामीण जलप्रदाय योजनाओं के सम्पूर्ण होने की संभावना है। राज्य के मरुस्थलीय पश्चिम भाग में पीने के पानी की समस्या अधिक जटिल है। राज्य सरकार इसके प्रति पूर्ण जागरूक व अपने सीमित साधनों में भी अधिकतम प्रयत्न करती रही है। राजस्थान नहर क्षेत्र में उपयु पीने का पानी सुलभ करने के उद्देश्य से डिग्गियों का भी निर्माण किया गया है।

30. राजस्थान के तीन प्रमुख नगरों – जयपुर, अजमेर एवं कोटा के लिए मास्टर-प्लान के प्रारूप तैयार कर लिए गये हैं। उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अलवर आदि नगरों के मास्टर-प्लान तैयार किये जा रहे हैं। राजस्थान नहर की क्षेत्रीय योजना तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। हनुमानगढ़ मंडी तथा इस क्षेत्र की अन्य अनेक आबादियों की योजनाएं तैयार की जा चुकी हैं। राजस्थान आवासन बोर्ड के गठन के बाद वर्ष 1971-72 में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर,

कोटा और अजमेर में 1 हजार 183 आवास-गृहों का कार्य हाथ में लिया गया है। वर्ष 1972-73 में 1 हजार 868 गृहों की योजना है। बोर्ड द्वारा अपंग, पुरस्कृत वीर सिपाहियों तथा मृत सिपाहियों के परिवारों को आवंटन में विशेष सुविधाएँ दी जा रही हैं।

41. भू-जल मण्डल द्वारा राज्य के विभिन्न भागों में सर्वेक्षण व कुएं गहरे करने तथा नलकूप निर्माण का कार्य प्रगति पर है। राज्य सरकार द्वारा सामूहिक ट्यूब-वैल योजना स्वीकृत की गई है जिसके अन्तर्गत एक साथ कई ट्यूब-वैल तैयार किये जाते हैं और उन्हें रियायती दरों पर कृषकों को बेचा जाता है। अलवर व नागौर क्षेत्रों में ऐसी ही दो योजनाएँ शुरू की गई हैं। 400 कुओं की योजना सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों के लिए तैयार की जा रही है।

42. इस समय राज्य के बारह जिलों में सड़कों व पुलों का निर्माण-कार्य तथा राजस्थान ग्रामीण सड़कों का कार्य प्रगति पर है। कुछ सड़कों पर कोलतार डालने का कार्य भी किया जायेगा। राज्य में सीमा-सड़कों का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है और आशा की जाती है कि आगे कार्यों के लिए भी वर्ष 1972-73 में प्रावधान केन्द्र से उपलब्ध होगा। वर्ष 1971-72 में भवन निर्माण कार्यों के लिए 343.66 लाख रुपये का प्रावधान था और इसके अन्तर्गत निर्मित होने वाले भवनों का निर्माण-कार्य चालू है जिनमें सरकारी अधिकारियों के लिए जयपुर में सचिवालय भवन व राज्य कर्मचारियों के लिए आवास-गृहों के निर्माण का कार्य भी सम्मिलित है।

43. इस वर्ष न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत राज्य सरकार ने सभी अनुसूचित उद्योगों में अकुशल श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 60 रुपये से बढ़ाकर 85 रुपये मासिक कर दिया है। अर्द्धकुशल व कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन क्रमशः 85 व 100 रुपये से बढ़ा कर 100 रुपये व 125 रुपये मासिक कर दिया है। ये परिवर्तित न्यूनतम वेतन की दरें 14 अगस्त, 1971 से प्रभावशील हो गई हैं। इस वर्ष कोन्ट्रेक्ट लेबर (रेगूलेशन एण्ड अबोलिशन) एक्ट, 1970 तथा इसके अन्तर्गत बने नियम 20 मार्च, 1971 से राज्य में लागू कर दिये गये हैं। इस अधिनियम के लागू होने से ठेके पर कार्य करने वाले हजारों श्रमिकों को वे ही काम, दशायें व वेतन दिया जायेगा, जो प्रमुख नियोजक अपने श्रमिकों को देते हैं तथा इससे ठेके पर काम करने वाले श्रमिकों का शोषण समाप्त करने में सहायता मिलेगी। यह हर्ष का विषय है कि संकटकालीन स्थिति में राज्य के श्रमिकों व प्रबन्धकों ने पूर्ण सहयोग दिया तथा पूरे वर्ष स्थिति में कोई औद्योगिक विवाद, तालाबन्दी व हड़ताल नहीं हुई। वर्ष 1971-72 में दो और जिला नियोजन कार्यालय जैसलमेर और बूंदी में खोले गये। गत वर्ष की तुलना में नियोजन की स्थिति सुधरी है।

44. समाज कल्याण की कई योजनाएँ राज्य में चल रही हैं जिनमें से कुछ उल्लेखनीय हैं। राज्य में बाल अधिनियम लागू हो गया है। इसके अन्तर्गत जयपुर में तथा अजमेर में बाल-गृह, विशेष स्कूल आदि भी स्थापित किये गये हैं। गर्भवती माताओं को पोषाहार की योजनाओं के

अन्तर्गत 1 लाख 50 हजार बच्चे एवं माताओं को 1 हजार 200 केन्द्रों के माध्यम से पो दिया जा रहा है। अगले वर्ष इस योजना को दुगुना करने का प्रस्ताव है। आदिवासी ब लिए आश्रम व स्कूल सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। हरिजन बस्तियों में नल व रोशनी भवन-निर्माण हेतु बिना ब्याज के ऋण दिये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों की सुवि लिए 7 आश्रम भी राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे हैं। इस हेतु लगभग 36 लाख रुपया किया जा रहा है। पिछड़ी जातियों के व्यक्तियों को निर्धारित अभ्यास की देख-रेख हेतु के सभी विभागों एवं राजकीय उपकरणों में रोस्टर प्रणाली लागू की गई है। अनुसूचित जाति जनजाति के कृषकों को सिंचाई-सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बैंकों द्वारा दिए जाने वा हजार रुपये तक के ब्याज का भुगतान समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है एवं जीणो करने के लिए 5 हजार रुपये के प्राप्त ऋण का ब्याज भी राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा

35. राज्य सरकार द्वारा घोषित, बेरोजगार स्नातकों एवं डिप्लोमाधारियों का पूल ब की योजना चल रही है जिसमें 760 व्यक्तियों का चयन हो चुका है। इस योजना के अन अभियांत्रिकी-स्नातकों को 250/- रुपये एवं डिप्लोमाधारियों को 150/-रुपये प्रतिमाह दर से दो वर्ष के लिए स्टाइपेण्ड दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त 1971-72 में अब तक 1 कार्मिकों को चुनिंदा सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों में प्रेक्टिकल ट्रेनिंग हेतु व्यवस्था की गयी और उन्हें क्रमशः 200/- रुपये व 150/-रुपये का वजीफा दिया जा रहा है। आई.टी.आ के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को अधिकाधिक रोजगार दिलाने हेतु मशीन टूल कारपोरेशन, अजमेर एक अनुबन्ध 1971-72 में किया गया है जिसके अनुसार 200 आई.टी.आई. अभ्यार्थि को प्रतिवर्ष रोजगार मिलेगा। इनमें से कुछ अभ्यार्थियों को के योग्य बनाने हेतु निगम प्रशिक्षण के लिए राजस्थान के बाहर भी भेजेगा जिसका व्यय राज्य सरकार वहन करेगी।

36. राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति नियन्त्रण में रही लेकिन अपराधों की संख में गत वर्ष की अपेक्षा कुछ वृद्धि अवश्य हुई है। पुलिस की कुख्यात डाकू-गिरोहों से इस अनेक बार मुठभेड़ हुई जिनमें 84 डाकू पकड़े गये व 12 डाकू मारे गये हैं।

37. कारागार विभाग द्वारा, बंदियों को समाज के लिए उपयोगी सभ्य नागरिक बनाने उद्देश्य से, कारागृहों में शिक्षा की उन्नति के लिए भिन्न स्तरों पर इस वर्ष कई ठोस कदम उठा गये हैं और उनसे लाभप्रद परिणाम निकले हैं।

38. राज्य के औद्योगिक और व्यावसायिक प्रगति के साथ-साथ पथ परिवहन का महत्व भी बढ़ता जा रहा है। वर्ष 1970-71 में गाड़ियों की संख्या 82 हजार 661 थी जो वर्ष 1971-72 में बढ़कर 97 हजार 752 हो गई है। राष्ट्रीयकृत मार्गों पर अवैधरूप से चलने वाली गाड़ियों की रोकथाम के लिये मोबाइल मजिस्ट्रेट्स की नियुक्ति की गई है जिसके फलस्वरूप ऐसी अवैध गाड़ियों की संख्या में कमी हुई है। राष्ट्रीयकृत मार्गों पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की

... चल रही है और इस वित्तीय वर्ष में निगम को लगभग 22 लाख रुपये का लाभ होगा। ... को बस सेवाओं की समुचित सुविधाएं मिल सकें इसके लिए निगम सचेष्ट है।

39. वर्ष 1971 में राज्य के पूर्वी एवं दक्षिणी-पूर्वी भाग में वर्षा लगभग सामान्य होने ... इन भागों में तो स्थिति सामान्य रही, किन्तु राज्य के पश्चिमी भाग में विशेषकर ..., जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, पाली, सिरोही, चूरू एवं गंगानगर में अभाव की ... रही। भीलवाड़ा जिले की आसीन्द तहसील के भी कुछ गाँव अभाव की स्थिति से ... हैं। कुल मिलाकर लगभग साढ़े चार हजार गाँव अभाव की स्थिति से प्रभावित हैं। ... में वर्षा ठीक हो जाने के कारण राज्य में लगभग चारे की स्थिति सामान्य है और पशु-... के लिए कोई विशेष व्यवस्था करना आवश्यक नहीं है। जिला जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, ... एवं बाड़मेर में पेयजल की व्यवस्था ट्रकों द्वारा भिजवाया जाकर एवं नलकूप चलाये जाकर ... 60 स्थानों पर की जा रही है। ग्राम्य-निर्माण कार्यक्रम एवं क्रेश योजना के अन्तर्गत चल ... कार्यों पर अभावग्रस्त लोगों को रोजगार मिलने के कारण कहीं सहायता कार्य प्रारम्भ नहीं ... गये हैं। वित्तीय वर्ष 1972-73 में यदि आवश्यकता समझी गई तो सहायता कार्य खोले ... सकेंगे।

40. प्रशासन में सुधार की दृष्टि से सचिवालय में प्रक्रिया सुधार कमेटी का गठन किया ... तथा कमेटी की सिफारिशों को लागू किया गया है। इसके अनुसार सचिवालय में ग्रुप-... प्रणाली प्रचलित हुई जिससे मामलों का निपटारा शीघ्र होगा और कार्य का स्तर ऊँचा होगा। ... के कर्मचारियों की स्ट्रेन्थ का मूल्यांकन एवं योजनाबद्ध कैरियर मैनेजमेण्ट जैसे आवश्यक ... पर भी कार्यवाही शुरू की गई। प्रशासन में स्फूर्ति लाने की दृष्टि से जनअभियोग निराकरण ... की भी स्थापना जुलाई, 1971 में की गई और इस अल्पावधि में प्राप्त 4 हजार शिकायतों ... में से लगभग आधे से अधिक मामलों का निपटारा कर दिया गया है। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ... भी आवश्यक कार्य किया जा रहा है। करीब 80 भ्रष्ट कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार की ... दी गई। अभी हाल ही में राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों को अन्तरिम राहत, मकान ... एवं परियोजना भत्ता देने का भी निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों के हित ... के लिए एक अलग से अधिकारी की भी नियुक्ति की गई है। तत्पश्चात् विभिन्न विभागों के ... 4 हजार कर्मचारी स्थायी किये जा चुके हैं।

41. इस सत्र का मुख्य कार्य, जिसके लिए आपको यहां आमंत्रित किया गया है वह ... वित्तीय वर्ष के लिए आय-व्ययक पर विचार-विमर्श करना एवं उसे पारित करना तथा ... सम्बन्धी कानून बनाना है। मुझे ऐसा विश्वास है कि आय-व्ययक पर विचार-विमर्श करते ... आप राज्य के सर्वांगीण विकास हेतु ध्यान रखेंगे जिसके लिए हम सभी कृत-संकल्प हैं। ... सरकार इस सत्र में राजस्थान कराधान विधियां (संशोधन) अध्यादेश, 1971; राजस्थान

यात्री तथा मालकर (संशोधन) अध्यादेश, 1971; राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) अध्यादेश, 1972 आदि भी आपके समक्ष विचार-विमर्श एवं उचित कार्यवाही के लिए प्रस्तुत करेगी।

42. मोटे तौर पर पिछले वर्ष की उल्लेखनीय घटनाओं और राज्य सरकार की उपलब्धियों का मैंने जिक्र किया है। अब हमें आने वाले वर्ष के कार्य-कलापों पर विचार करना है और राजस्थान के चहुँमुखी विकास की दिशा में कार्य करना है। जनहित में आप सबका सदैव की भांति पूर्ण सहयोग प्राप्त हो तथा आपके विचार-विमर्श में सफलता मिले यही मेरी कामना है।

43. राजस्थान विधान सभा में मेरा यह अन्तिम अभिभाषण है। मेरे कार्यकाल के पाँच वर्षों की अवधि में जो सहयोग और सद्भावनाएँ सदन के सदस्यों से प्राप्त हुई, उसके लिए मैं आभारी हूँ। आपके स्नेह की सुखद स्मृति की अमिट छाप मेरे हृदय में सदा-अंकित रहेगी। राजस्थान अपने विकास एवं समृद्धि के प्रशस्त मार्ग पर अबाध गति से अग्रसर होता रहे, यही मेरी हार्दिक कामना सदैव रहेगी।

जय हिन्द।

ooo